

F.No.20011/1/2000-Estt(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi 110001
March 27, 2001

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Seniority of persons absorbed
after being on deputation.**

The undersigned is directed to say that according to our O.M.No.20020/7/80-Estt(D) dated May 29, 1986 (copy enclosed) in the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "transfer on deputation/transfer"), his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has, however, been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis in his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the condition that he will be given seniority from

- the date he has been holding the post on deputation,

OR

- the date from which he has been appointed on a regular basis to same or equivalent grade in his parent department,

whichever is later.

2. The Supreme Court has in its judgement dated December 14, 1999 in the case of *Shri S.I. Rooplal & Others Vs. Lt. Governor through Chief Secretary, Delhi, JT 1999 (9) SC 597* has held that the words "whichever is later" occurring in the Office Memorandum dated May 29, 1986 and mentioned above are violative of Articles 14 and 16 of the Constitution and, hence, those words have been quashed from that Memorandum. The implications of the above ruling of the Supreme Court have been examined and it has been decided to substitute the term "whichever is later" occurring in the Office Memorandum dated May 29, 1986 by the term "whichever is earlier".

3. It is also clarified that for the purpose of determining the equivalent grade in the parent department mentioned in the Office Memorandum dated May 29, 1986, the criteria contained in this Department Office Memorandum No.14017/27/75-Estt(D)(pt) dated March 7, 1984 (copy enclosed), which lays down the criteria for determining analogous posts, may be followed.

4. These instructions shall take effect from the December 14, 1999 which is the date of the judgement of the Supreme Court referred to above.

5. In so far as personnel serving in Indian Audit and Accounts Departments are concerned, these instructions are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India. However, these orders (in keeping with paragraph 4 of the Office Memorandum dated May 29, 1986 as referred to above) will not be applicable to transfers within the Indian Audit and Accounts Department which are governed by orders issued by the C&AG from time to time.

6. The above instructions may be brought to the notice of all concerned for information, guidance and necessary action.



(K.K. JHA)

DIRECTOR(Establishment)

To

All Ministries/Departments of the Government of India

Copy to:-

1. The President's Secretariat, New Delhi.
2. The Prime Minister's Office, New Delhi.
3. The Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
4. The Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
5. The Registrar General, The Supreme Court of India.
6. The Registrar, Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi
7. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi with reference to their letter No.248/Audit(Rules)Gr.IV 16-98 dated 5.10.2000.
8. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi with reference to their letter No.F.2/7/2000-S.II dated 28.2.2001.
9. Ministry of Home Affairs (UTP), New Delhi with reference to their D.O. letter No.14040/32/99-UTP dated 7.1.2000.
10. The Staff Selection Commission, New Delhi.
11. National Commission for SCs/STs, New Delhi.
12. National Commission for OBCs, New Delhi.
13. All State Governments/Union Territory Administrations.
14. All attached/subordinate offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions/Ministry of Home Affairs.
15. All Sections in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
16. The Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 9, Ashoka Road, New Delhi.
17. Facilitation Center, DoP&T (**20 copies**)
18. NIC (DoP&T) for placing this Office Memorandum on the website of DoP&T.
19. Establishment(D) Section, DOP&T (**500 copies**)

संख्या 20011/1/2000-स्थापना(घ)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 27, 2001

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: प्रतिनियुक्ति पर रहने के पश्चात् संविलियत कर्मचारियों की वरिष्ठता ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के मई 29, 1986 के का.ज्ञा.संख्या 20020/7/80-स्था.(घ)(प्रति संलग्न) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति के मामले में जो किसी कार्यालय में आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और बाद में वहीं पर संविलियत कर लिया जाता है (अर्थात् जहां पर संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण" का प्रावधान है), तो जिस ग्रेड में वह संविलियत किया गया है उस ग्रेड में उसकी वरिष्ठता की गणना, सामान्यतः उस ग्रेड में संविलियत किए जाने की तारीख से की जाएगी । तथापि, यदि उसने अपने मूल विभाग में (संविलियन की तारीख को) उसी समान अथवा समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर पहले से ही पद धारित किया हुआ है, तो ग्रेड में की गई ऐसी नियमित सेवा को भी वरिष्ठता निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जाएगी:-

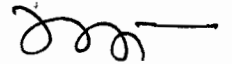
- जिस तारीख से वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारित किए हुए है,
अथवा
- जिस तारीख से उसे अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर समान अथवा समकक्ष ग्रेड में नियुक्त किया गया है,

इनमें से जो भी बाद में हो :-

2. उच्चतम न्यायालय ने श्री एस.आई. रूपलाल तथा अन्य बनाम उप राज्यपाल, मुख्य सचिव, दिल्ली के माध्यम से, जे.टी., 1999 (9) एस.सी. 597 के मामले में यह माना है कि मई 29, 1986 के का.ज्ञा. में आए और ऊपर उल्लिखित शब्द "इनमें से जो भी बाद में हो" संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं और अतः ये शब्द उस का.ज्ञा. से हटा दिए जाते हैं । उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के निहितार्थ की जांच-पड़ताल की गई है और मई 29, 1986 के का.ज्ञा. में आए शब्दों "इनमें से जो भी बाद में हो" के स्थान पर "इनमें से जो भी पहले हो" शब्दों को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

.....2/-

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मई 29, 1986 के का.ज्ञा. में उल्लिखित मूल विभाग में समकक्ष ग्रेड का निर्धारण करने के लिए इस विभाग के मार्च 7, 1984 के का.ज्ञा.संख्या 14017/27/75-स्था.(घ)(पार्ट) (प्रति संलग्न) में दिए गए सदृश पदों को निर्धारित किए जाने वाले मानदंडों का अनुसरण किया जाए ।
4. ये अनुदेश उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय की तारीख अर्थात् दिसम्बर 14, 1999 से प्रभावी होंगे ।
5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभागों में कार्यरत कार्मिकों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं । तथापि, ये आदेश (ऊपर उल्लिखित मई 29, 1986 के का.ज्ञा. के पैरा 4 के मद्देनज़र) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के आंतरिक स्थानांतरण पर लागू नहीं होंगे जो कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा अधिशासित होते हैं ।
6. उपर्युक्त अनुदेशों को जानकारी, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए ।



(के.के. झा)

निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग । 3/11/99